



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 663]

नई दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 22, 2008/पौष 1, 1930

No. 663]

NEW DELHI, MONDAY, DECEMBER 22, 2008/PAUSA 1, 1930

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 दिसम्बर, 2008

सं. 134/2008-सीमाशुल्क

सा.का.नि. 869(अ).— अभिहित प्राधिकारी, सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 (1975 का 51) की पहली अनुसूची के शीर्ष 6907 या 6908 या 6914 के अंतर्गत आने वाले, चीन जनवादी गणराज्य (चाइना पीआर) और यूनाईटेड अरब अमीरात (यूएई) (जिसे इसमें इसके पश्चात संबद्ध देश भी कहा गया है) में मूलतः उदगमित या वहां से निर्यात किए गए, विट्रीफाइड औद्योगिक टाइलों से भिन्न विट्रीफाइड/ पोर्सिलेन टाइलों (जिसे इसमें इसके पश्चात संबद्ध माल भी कहा गया है) के आयात के मामले में भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग I, खंड 1, तारीख 23 अप्रैल, 2008 में प्रकाशित अपने अंतिम जांच परिणाम अधिसूचना सं० 15/17/2006-डीजीएडी, तारीख 21 अप्रैल, 2008 में इस निर्णय पर पहुंचे थे कि,—

- (i) यूएई से कोई पाटन नहीं हुआ था;
- (ii) वर्तमान उपाय समाप्त किए जाने की स्थिति में चाइना पीआर से पाटित कीमतों पर भारतीय बाजार में संबद्ध माल के प्रवेश की संभावना थी;
- (iii) लागू पाटनरोधी उपायों के बावजूद घरेलू उद्योग को वर्तमान में पर्याप्त क्षति हो रही थी। रिकार्ड में भी ऐसा कोई साक्ष्य नहीं था जिससे इस बात का पता चलता कि पाटनरोधी शुल्क समाप्त किये जाने की स्थिति में पाटन या घरेलू उद्योग को क्षति समाप्त हो जायेगी या उसकी पुनर्नवृत्ति होने की संभावना नहीं रहेगी;

और घरेलू उद्योग से क्षति लोप करने के लिए चाइना पीआर से उदगमित या वहां से निर्यात किए गए संबद्ध माल पर प्रतिपाटन शुल्क अधिरोपित करने की सिफारिश को जरूरी समझा था;

और जबकि अभिहित प्राधिकारी के पूर्वोक्त निष्कर्षों के आधार पर केन्द्रीय सरकार ने, भारत सरकार के (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं० 82/2008-सीमाशुल्क, तारीख 27 जून, 2008, जो कि सा०का०नि० 485 (अ), तारीख 27 जून, 2008, के द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित हुई थी, के द्वारा संबद्ध माल पर प्रतिपाटन शुल्क लगाया था;

और जबकि, मै0 फोशन लिहुआ सेरामिक्स कं. लि. चाइना पीआर (उत्पादक), मै0 फोशन हेनरी ट्रेडिंग कं. चाइना पीआर (निर्यातक) के साथ मै0 अंजनेय ट्रेडिंग पीटीई लि0, सिंगापुर (निर्यातक) ने सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उस पर प्रतिपाटित शुल्क का निर्धारण और संग्रहण तथा क्षति का अवधारण) नियम, 1995 के नियम 22 के तहत उनके द्वारा किये गये निर्यातों की समीक्षा का निवेदन किया है तथा अभिहित प्राधिकारी ने भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग I, खंड 1 तारीख 11 नवम्बर, में प्रकाशित न्यू शिपर समीक्षा अधिसूचना सं0 15/23/2008-डीजीएडी, तारीख 11 नवम्बर, 2008 द्वारा न्यू शिपर समीक्षा के पूरे होने तक विषयगत माल का, उक्त मै0 फोशन लिहुआ सेरामिक्स कं. लि. (उत्पादक), मै0 फोशन हेनरी ट्रेडिंग कं. चाइना पीआर (निर्यातक) के साथ मै0 अंजनेय ट्रेडिंग पीटीई लि0, सिंगापुर (निर्यातक) द्वारा सभी निर्यातों पर अनंतिम मूल्यांकन की सिफारिश की है;

अतः अब केन्द्रीय सरकार सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उस पर प्रतिपाटित शुल्क का निर्धारण और संग्रहण तथा क्षति का अवधारण) नियम, 1995 के नियम 22 के उपनियम (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पूर्वोक्त निष्कर्षों पर विचार करने के पश्चात यह आदेश देती है कि अभिहित प्राधिकारी द्वारा की जा रही न्यू शिपर समीक्षा के परिणाम आने तक, मै0 फोशन लिहुआ सेरामिक्स कं. लि. चाइना पीआर द्वारा उत्पादित तथा मै0 अंजनेय ट्रेडिंग पीटीई लि0, सिंगापुर के जरिए मै0 फोशन हेनरी ट्रेडिंग कं. चाइना पीआर द्वारा निर्यातित, उक्त सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम के प्रथम अनुसूची के शीर्ष 6907 या 6908 या 6914 के अंतर्गत आने वाले संबद्ध माल की सभी निर्यातों का भारत में आयात होने पर न्यू शिपर समीक्षा पूर्ण होने तक अनन्तिम मूल्यांकन किया जायेगा।

2. अनन्तिम मूल्यांकन के लिए ऐसी गारंटी आवश्यक होगी, जो सीमाशुल्क के सक्षम अधिकारी द्वारा समीक्षा के पूरे होने पर अभिहित प्राधिकारी द्वारा पूर्व प्रभावी रूप से निश्चयात्मक प्रतिपाटन शुल्क अधिशेषित करने की स्थिति में अपर्याप्तता की अदायगी के लिए समुचित समझी गई हो।

3. यदि अभिहित प्राधिकारी न्यू शिपर समीक्षा के पूरे होने पर प्रतिपाटन शुल्क की सिफारिश करते हैं, तो मै0 फोशन लिहुआ सेरामिक्स कं. लि. चाइना पीआर (उत्पादनकर्ता), मै0 अंजनेय ट्रेडिंग पीटीई लि0, सिंगापुर (निर्यातकर्ता) के जरिए मै0 फोशन हेनरी ट्रेडिंग कं. चाइना पीआर (निर्यातकर्ता) से भारत में आयातित संबद्ध माल के आयातों पर आयातक उक्त न्यू शिपर समीक्षा के प्रारंभ की तारीख से प्रतिपाटित शुल्क की रकम अदा करने के लिए जिम्मेदार होगा।

[फा. सं. 354/214/2001-टीआरयू (पार्ट III)]

उन्मेष बाघ, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd December, 2008

No. 134/2008-CUSTOMS

G.S.R. 869(E).— Whereas in the matter of imports of vitrified and porcelain tiles, other than vitrified industrial tiles (hereinafter referred to as the 'subject goods'), falling under headings 6907 or 6908 or 6914 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), originating in or exported from the People's Republic of China (China PR) and United Arab Emirates (UAE) [hereinafter referred to as the subject countries] and imported into India, the

designated authority in its sunset review final findings No.15/17/2006-DGAD, dated 21st April, 2008, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part I, Section 1, dated the 23rd April, 2008, had inter alia come to the conclusion that –

- (i) there was no dumping taking place from UAE;
- (ii) the subject goods were likely to enter Indian market at dumped prices from China PR, should the present measures be withdrawn;
- (iii) in spite of the anti-dumping measures in place, there existed significant current injury to the domestic industry. There was also no evidence on record to suggest that ~~dumping~~ or the injury to the domestic industry would cease to exist or was not likely to recur in case the anti-dumping duties were discontinued;

and had considered it necessary to recommend continued imposition of the anti-dumping duty on the subject goods originating in, or exported from, China PR in order to remove injury to the domestic industry;

And whereas, on the basis of the aforesaid findings of the designated authority, the Central Government had imposed an anti-dumping duty on the subject goods vide notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 82/2008-Customs, dated the 27th June, 2008, published in Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide number G.S.R.485(E) of the same date;

And whereas, M/s Foshan Lihua Ceramics Co. Ltd., China PR (producer), M/s Foshan Henry Trading Company, China PR (exporter) through M/s Anjaneya Trading PTE Ltd., Singapore (exporter) have requested for review in terms of rule 22 of the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995 in respect of exports made by them, and the designated authority vide new shipper review notification No. 15/23/2008-DGAD, dated the 11th November, 2008, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part I, Section 1, dated the 11th November, 2008, had recommended provisional assessment of all exports of the subject goods made by the said M/s Foshan Lihua Ceramics Co. Ltd., China PR (producer), M/s Foshan Henry Trading Company, China PR (exporter) through M/s Anjaneya Trading PTE Ltd., Singapore (exporter) till the completion of the new shipper review;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-rule (2) of rule 22 of the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, the Central Government, after considering the aforesaid recommendation of the designated authority, hereby orders that pending the outcome of the said new shipper review by the designated authority, vitrified and porcelain tiles, other than vitrified industrial tiles, falling under headings 6907 or 6908 or 6914 of the First Schedule to the said Customs Tariff Act, produced by M/s Foshan Lihua Ceramics Co. Ltd., China PR and exported by M/s Foshan Henry Trading Company, China PR through M/s Anjaneya Trading PTE Ltd., Singapore, when imported into India, shall be subjected to provisional assessment till the new shipper review is completed.

2. The provisional assessment may be subject to such security or guarantee as the Assistant Commissioner of Customs or Deputy Commissioner of Customs, as the case may be, deems fit for payment of the deficiency, if any, in case a definitive anti-dumping duty is imposed retrospectively on completion of investigation by the designated authority.

3. If the designated authority recommends anti-dumping duty after completion of the said new shipper review, the importer shall be liable to pay the amount of such anti-dumping duty imposed on all imports into India of the subject goods from M/s Foshan Lihua Ceramics Co. Ltd., China PR (producer) and M/s Foshan Henry Trading Company, China PR (exporter) through M/s Anjaneya Trading PTE Ltd., Singapore (exporter), from the date of initiation of the said new

[F. No. 354/214/2001-TRU (Pt. III)]

UNMESH WAGH, Under Secy.